

डिप्टी कलेक्टर ने सुनीं आम जनों की समस्याएं
उमरिया, ईएमएस। साप्ताहिक जनसुनार्ड कार्यक्रम में डिप्टी
कलेक्टर मीनांकी इंगले, सीईओ जनपद पंचायत करकेली हरनीत
कौर कलटी ने जिले के दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को
सुना तथा उसका विवाकरण भी कराया।

संपादकीय

फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान

केंद्रीय | प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मध्य प्रदेश के शराब कारोबारी से जुड़े हुए फर्जीवाड़ को लेकर 11 शराब कारोबारी के 18 टिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में 49 करोड़ 42 लाख रुपये की धोखाघढ़ी और सरकारी खजाने में और वह रुपये की डैक्टी डालना का मामला सामने आया है। इंडी में मनी लॉइंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की है। जांच एंजेसी को छापे के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और उसकारी खजाने में और वह करोड़ों-अरबों रुपए का किया गया घोटाला मध्य प्रदेश में उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश में 2015-16 में पहली बार यह मामला उजागर हुआ था। उस समय इस मामले को दबा दिया गया था। हाल ही में इंडी की टीम ने जब छापा मारकर जांच शुरू की। उसके बाद एक के बाद एक नए फर्जीवाड़ की परतें खुलकर सामने आयी थीं। इन्हें 2015-16 से 2017-18 के बीच चालानों में फर्जीवाड़ किया गया। जिससे सरकार को अरबों रुपए का परतें खुलकर सामने आया, तब तकलीन आबकारी मंत्री की भूमिका संदेहासपूर्ण रही। आबकारी विभाग के जिस अधिकारी संजीव दुबे की सरपरस्ती में आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे, 2017 में उसकी एफएसआर दर्ज हुई। योर्किंग इस लूट में आबकारी विभाग के महत्वपूर्ण पदों में बैठे लोग शामिल थे अतः मामले को दबा दिया गया। जब यह मामला उजागर हुआ, तब शराब टेकेदारों ने 22 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जाकर मामले को दबा दिया था। इस मामले को दबा दिया गया के अधिकारी और तकलीन मंत्री की भूमिका थी। उस समय सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों ने इस लूट में अपना-अपना हिस्सा वसूल किया था। 2017 से यह मामला इंडी के पास लंबित पड़ा हुआ था। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बार-बार जानकारी मांगी गई। उसके बाद भी आबकारी विभाग द्वारा इंडी को समय पर जानकारी नहीं दी जा रही थी। इंडी ने शराब कारोबार से जुड़े टेकेदारों और अधिकारियों को जांच अपने स्तर पर कर 18 टिकानों पर छापेमारी की है। आपी तक लगभग 40 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व को नुकसान पहनचाने को इंडी ने जस किया है। इस मामले की जिस तरह से इंडी जांच कर रही है, उससे अरबों रुपए की धोखाघढ़ी के नए मामले उजागर होने की संभावना इंडी के अधिकारियों ने व्यक्त की है। शराब कारोबारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा राजनेताओं की मिली भगत से बड़े खाते रुपए के घोटाले हर राज्य में हो रहे हैं। दलिलों का मामला पछले कई वर्षों से चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश में भी हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला शराब कारोबारियों और आबकारी विभाग की मिली भगत से नुकसान हो रहा है। शराब कारोबार में सरकारी खजाने को सुनियोजित रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर शराब कारोबार से जुड़े किस तरह के अपराध होते हैं, यह मामला सामने आ चुका है। केंद्रीय परिवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी विभाग में चल रहे घोटाले की टैकिंग पिछले कई महीनों से की जा रही थी। सही कारोबारी से कार्रवाई हुई, तो इसमें बड़े-बड़े खुलासे होंगे। यह मामला मध्य प्रदेश का है। देशरपर में इसी तरीके से फर्जी रुपयों के जरिए बड़े घैमाने पर सरकारी खजाने में घोटाले किए जा रहे हैं। ट्रेजरी में चालान से और ऑनलाइन ट्रांसफर की गई राशि का मिलान कई-कई वर्षों तक नहीं हो पाता है। अधिकारियों की कोई रुपयी नहीं होती है। जिस तरीके से ट्रेजरी में लेन-देन बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय और वित्त विभाग के पास जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार के खातों में जो रकम जमा होती है, उसका मिलान करने का सिस्टम नहीं होता है। इस दिन बाजार में अरबों रुपए की धोखाघढ़ी के नए मामले उजागर होने की संभावना इंडी के अधिकारियों ने व्यक्त की है। शराब कारोबारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा राजनेताओं की मिली भगत से बड़े घोटाले हो रहे हैं। दलिलों का मामला पछले कई वर्षों से चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश में भी हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला शराब कारोबारियों और आबकारी विभाग की मिली भगत से होता है। शराब कारोबार में सरकारी खजाने को सुनियोजित रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर शराब कारोबार से जुड़े किस तरह के अपराध होते हैं, यह मामला सामने आ चुका है। केंद्रीय परिवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी विभाग में चल रहे घोटाले की टैकिंग पिछले कई महीनों से की जा रही थी। सही कारोबारी से कार्रवाई हुई, तो इसमें बड़े-बड़े खुलासे होंगे। यह मामला मध्य प्रदेश के अपराधरपर में इसी तरीके से फर्जी रुपयों के जरिए बड़े घैमाने पर सरकारी खजाने में घोटाले किए जा रहे हैं। ट्रेजरी में चालान से और ऑनलाइन ट्रांसफर की गई राशि का मिलान कई-कई वर्षों तक नहीं हो पाता है। अधिकारियों की कोई रुपयी नहीं होती है। जिस तरीके से ट्रेजरी में लेन-देन बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय और वित्त विभाग के पास जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार के खातों में जो रकम जमा होती है, जिससे यह पता लगे, कहां पर किस लेवल पर गड़बड़ी हो रही है। इंडी ने इस मामले में छापे डाले हैं। निश्चित रूप से नए-नए खुलासे होंगे। धोखाघढ़ी और दस्तावेजों में होरा-फेरी करके राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हर महीने पहुंचाया जा रहा है। उसमें रोक लगेगी, यही आशा की जा सकती है।

- सनत जैन

राज काज

राहुल गांधी का कश्मीर दौरा, मोदी के लिए मुसीबत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को घोटा गए। वहां पर उहाँने आंतकावादी हमले में घोटा हुए लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उनके जल्द दरवाजे होने की कामना की। उनके परिवार के नेता भी मुलाकात कर हर संभव सहायता करने की पेशकश की। ध्यानमंत्री वर्कर बड़ी गांधी घोटा हुआ, उत्तर वह सर्वदलीय थैंक छोड़कर बिहार में उत्तरांचल और शिल्पव्याप करेंगे। यहां पर मध्य प्रदेश की गांधी घोटा हुआ। उहाँने दूंप कर दबाव लगाया। जिसके कारण दो बार ट्रॉप को अपनी धोयावाड़ों से कुछ दिनों के अंदर संशोधित करना पड़ा। ऐसी बेज़ती इसके पहले कार्ती अमेरिका की नहीं हुई। जो ट्रॉप के शासनकाल में अमेरिका की हो रही है।

- सनत जैन

चीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप की हवा निकाली

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा थी नहीं होगा। चीन उहाँ इस तरह के ऊपर उत्तरांचल के टैरिफ लगाए। चीन जैने जो राजनीति की जारी रही है। इस पर अतिरिक्त आंतकावादी हमले के नेता भी पूछ रहे हैं। इस पर अतिरिक्त आंतकावादी हमले के नेता भी पूछ रहे हैं। उहाँने दूंप कर दबाव लगाया। जिसके कारण दो बार ट्रॉप को अपनी धोयावाड़ों से कुछ दिनों के अंदर संशोधित करना पड़ा। ऐसी बेज़ती इसके पहले कार्ती अमेरिका की नहीं हुई। जो ट्रॉप के शासनकाल में अमेरिका की हो रही है। चीन के नुकसान रुकावा करने की जारी रही है।

ममता और रॉबर्ट वाडा ने पहलगाम की बीटना का सत्य बताया

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले में 28 पर्टक जारी है। आंतकी परावादियों ने धर्म पूछ रखी जारी है। इस पर अतिरिक्त आंतकावादी हमले के नेता भी पूछ रहे हैं। उहाँने दूंप कर दबाव लगाया। जिसके कारण दो बार ट्रॉप को अपनी धोयावाड़ों से दूंप कर दबाव लगाया। ऐसी बेज़ती इसके पहले कार्ती अमेरिका की नहीं हुई। जो ट्रॉप के शासनकाल में अमेरिका की हो रही है। चीन के नुकसान रुकावा करने की जारी रही है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले में 28 पर्टक जारी है।

आंतकी परावादियों ने धर्म पूछ रखी जारी है। इस पर अतिरिक्त आंतकावादी हमले के नेता भी पूछ रहे हैं। उहाँने दूंप कर दबाव लगाया। जिसके कारण दो बार ट्रॉप को अपनी धोयावाड़ों से दूंप कर दबाव लगाया। ऐसी बेज़ती इसके पहले कार्ती अमेरिका की नहीं हुई। जो ट्रॉप के शासनकाल में अमेरिका की हो रही है। चीन के नुकसान रुकावा करने की जारी रही है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले में 28 पर्टक जारी है।

आंतकी परावादियों ने धर्म पूछ रखी जारी है। इस पर अतिरिक्त आंतकावादी हमले के नेता भी पूछ रहे हैं। उहाँने दूंप कर दबाव लगाया। जिसके कारण दो बार ट्रॉप को अपनी धोयावाड़ों से दूंप कर दबाव लगाया। ऐसी बेज़ती इसके पहले कार्ती अमेरिका की नहीं हुई। जो ट्रॉप के शासनकाल में अमेरिका की हो रही है। चीन के नुकसान रुकावा करने की जारी रही है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले में 28 पर्टक जारी है।

आंतकी परावादियों ने धर्म पूछ रखी जारी है। इस पर अतिरिक्त आंतकावादी हमले के नेता भी पूछ रहे हैं। उहाँने दूंप कर दबाव लगाया। जिसके कारण दो बार ट्रॉप को अपनी धोयावाड़ों से दूंप कर दबाव लगाया। ऐसी बेज़ती इसके पहले कार्ती अमेरिका की नहीं हुई। जो ट्रॉप के शासनकाल में अमेरिका की हो रही है। चीन के नुकसान रुकावा करने की जारी रही है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले में 28 पर्टक जारी है।

तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया गया
उज्जैन, ईएमएस। मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा एवं उद्यम लिंगि
फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधववर्ग में
तेजस्वी कार्य में कें अंतर्गत तेजस्वी जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। इसमें उज्जैन
जिले के 65 विद्यालयों की छात्र-छात्राओं की 56 टीमों के द्वारा उद्यमिता से संबंधित नवाचार
प्रोजेक्ट और मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई।

फटाफट खबरें

शिविर लगाकर दी कलौंजी
की खेती की जानकारी

अशोकनगर, ईएमएस। राज्य औषधि
पादप बोर्ड मध्य प्रदेश शासन
द्वारा एयर योजना अन्तर्गत एक जिला
एक अशेषीय उत्पाद योजना
अन्तर्गत अयुष विभाग अशोकनगर
द्वारा औषधीय पौधों की खेती कलौंजी
जो कि एक औषधि वस्त्र माला पैदा है।
खेतों का एक दिवारीय खस्तहायता
समूहों का प्रशिक्षण मुंगावतों के
बीचीयुक्त जिला अशोकनगर में
मास्टर ट्रेनर आदित्य सिंह ने मंगलवार को
कलेक्टर के द्वारा में कृषि, संग्रहण,
भंडारण विधान, विक्रय आदि
विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
मास्टर ट्रेनर भारती परिवार द्वारा
औषधीय फसलों की तैयारी के बारे में
एवं उत्पादन के बारे में सम्झत
जानकारी प्रदान की गई। औषधीय
की उपर्युक्त ताके संबंध में
जानकारी गई, औषधीय फसलों
के लाभ के बारे में बताया गया।
मौसम के अनुसार औषधीय फसलों
के उत्पादन के बारे में बताया गया।
प्रशिक्षण में 30 से अधिक
खस्तहायता समूहों की सदस्य
समिलित हुई।

बैंकिंग सहायक मोनिका
महेश्वरी को किया बर्खास्त
खरगोन, ईएमएस। जिला सहकारी
केंद्रीय बैंक की मण्डी शाया
खरगोन पर दृष्ट्यांकित गहरायक
मोनिका माहेश्वरी को लक्षी अवधि से
अपने पदस्थिती स्थान से नियमित
स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से
अनुपस्थित रहने के कारण तकाल
प्रभाव से सेवा से बरकरार कर दिया
गया है। बैंक प्रबंध संचालक पीएस
धनवाल द्वारा बताया गया कि
मोनिका माहेश्वरी अपने कर्तव्य स्थल
से मई 2022 से अनाधिकृत रूप से
अनुपस्थित थी। इस सांबंध में अपने
बार सूचना पत्र देते हुए कर्तव्य स्थल
पर उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।
समाचार पत्रों के माध्यम से भी उन्हें
अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित
होने हेतु आगाह किया गया। किन्तु
वह किन्तू रूप से अनुपस्थित रही,
इस कारण बैंक कर्मचारी सेवा
नियमानुसार प्रकरण बैंक स्टॉफ उप
समिति में रखा जाकर मोनिका
महेश्वरी को सेवा से बरकरार करने
का प्रारंभिक लिया गया है। बैंक
कर्मचारियों को आगाह किया है कि
कोई भी कर्मचारी बिना सक्षम
स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्ताव
नहीं करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई
की जाएगी।

**प्रौद्योगिकी अधिकारी को
सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाइ**
खरगोन, ईएमएस। जिला प्रौद्योगिकी
अधिकारी श्री गुरु विदाइ ने अपने
अधिकारी की आयु पूर्ण कर 20 अप्रैल
2025 को सेवानिवृत्ति हो गई है। उनकी
सेवानिवृत्ति पर उन्हें भारतीय बिदाइ की
गई। बिदाइ कार्यक्रम में जिला शिक्षा
अधिकारी श्री एसके कानून, जिला
परिवर्जना समन्वयक श्री रमेशराज
सेव, एपीसी श्री देवधान पाठीदार, जेर्ड
श्री मुमुक्षु खान, एपीसी श्री पुरुषोदाम
पाठीदार सहित समर्त राज शिक्षा
अधिकारी श्री रामेश तथा
विकासरख राज-समन्वयक
(राजस्तान) एवं श्री रामजीत अर्य
विकासरख जोत समन्वयक, विकास
रख खरगोन, स्टाफ उपस्थित हुए।

► ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए सामुदायिक भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए

वाटरमेन को 5 माह का नहीं मिला मानदेय, जनसुनवाई में की शिकायत

खरगोन, ईएमएस। कलेक्टर कार्यालय परिसर
में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान 61
आवेदकों ने अपने समस्यामुलक अवेदन
अधिकारियों को सौंपे।

बड़वाह की रोशनी कलमे शिकायत लेकर आयी थी
कि उसका पति रवि कलमे उसकी एक साल की

बेटी को लेकर 20 अप्रैल 2025 से लापता है।

पुलिस उसके पाति व बेटी की तलाश में कोई मदद

नहीं कर रही है। ग्राम पंचायत तुड़ाका के रोकेश

चौहान ने मार्च 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक

बतौर वाटरमेन सेवाएं देने के दौरान वर्म मानदेय 7

हजार रुपये प्रतिमाह नहीं मिलने की शिकायत की

है। चौहान ने अपने 35 हजार रुपये मानदेय दिलाए

जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत गोपालपुरा के

ग्रामीण शिकायत तेकर आये थे कि पंचायत के उप

सरपंच राकेश एवं सचिव नियमन्वयक

भवन का निर्माण शासकीय भूमि पर न किया जा रहा है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाये। बैड़ीपुरा भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है। उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्राम कोटेवाडा के किसान सरदार पिता बनसिंह शिकायत लेकर आये थे कि अन्याय तक उप

सरपंच राकेश एवं सचिव नियमन्वयक भवन का निर्माण शासकीय भूमि पर किया जा रहा है।

ग्राम कोटेवाडा के किसान सरदार पिता बनसिंह शिकायत लेकर आये थे कि अन्याय तक उप

सरपंच राकेश एवं सचिव नियमन्वयक भवन का निर्माण शासकीय भूमि पर किया जा रहा है।

ग्राम कोटेवाडा के किसान सरदार पिता बनसिंह शिकायत लेकर आये थे कि अन्याय तक उप

सरपंच राकेश एवं सचिव नियमन्वयक भवन का निर्माण शासकीय भूमि पर किया जा रहा है।

ग्राम कोटेवाडा के किसान सरदार पिता बनसिंह शिकायत लेकर आये थे कि अन्याय तक उप

सरपंच राकेश एवं सचिव नियमन्वयक भवन का निर्माण शासकीय भूमि पर किया जा रहा है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल रही है।

ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए यह भवन शासकीय भूमि पर ही बनाया जाए। बैड़ीपुरा

भीकरान के शिवाराम प्रजापत शिकायत लेकर आये थे कि उनकी आयु 83 वर्ष की हो चुकी है।

उनकी आयु के अन्य लागों को 1500 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह ही पेंशन मिल

एसआईटी करेगी लव जिहाद की जांच

भोपाल, ईमएस। इंदौर और भोपाल में कॉलेज छात्रों से हुए लव जिहाद का मामला ईन्डिया यूनिवर्सिटी में है। जब आक्रमण के चलते पुलिस को श्री ताबिदोत्ते एसआईटी गठित करना पड़ी थी अब एसआईटी इस मामले की तेजी से जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि एसआईटी मामले की जांच के लिए इंदौर भी जाएगी।

4 मई को मनेगा भगवान चित्रगृह का प्रकटोत्सव

भोपाल, ईमएस। मध्यप्रदेश युवा कारब्यथ संगठन 4 मई को भगवान चित्रगृह का प्रकटोत्सव मनागा। इस अवसर पर जवाहर चौक के चित्रगृह मंदिर से श्रीभायामा विकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विष्णु केलाश सारंग करेगा। श्रीभायामा तें ऊंट, घोड़, घर्षी और भगवान चित्रगृह की 10 फीट ऊंची प्रतीमा आकर्षण का केंद्र होंगी। श्रीभायामा जवाहर चौक से रंगमहल चौराहा, टीटी नगर थाना, व्यू मार्केट, जी.टी.बी. चौराहा होते हुए चित्रगृह मंदिर पर समाप्त होंगी।

भोपाल 08

सीएमडॉ मोहन करेंगे राशि ट्रांसफर, खाते में आएंगे 600 करोड़

आज श्रमिक परिवारों के मिलेगी बड़ी सौगात



भोपाल, ईमएस।

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव बुधवार को श्रमिक परिवारों को राशि वितरित करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों में 600 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। यह कार्यक्रम धर जिले के उम्रबन में होगा। जहाँ मुख्यमंत्री सिंगल बिल के जरिए योजना की राशि जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में श्रम व पंचायत एवं ग्रामीण समंजस मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी जूदा होंगे।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, प्रदेश में असंचारित बेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अतंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें अनुग्रह सहायता के अंतर्गत दुर्टा में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और सामाजिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसी तहत स्थायी अंगता पर 2 लाख रुपये और आशिक स्थायी अंगता पर एक लाख रुपये, अलेखि

एमपीपीएसी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन को किया रद्द

भर्ती में आयुष को शामिल करने की मांग

भोपाल, ईमएस।

मध्यप्रदेश 1 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी किए गए विज्ञापन को निरसन कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश से प्राप्त पत्र और भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक अहर्ताओं में किए गए संसोधनों के आधार पर लिया है। शैक्षणिक आयोग में बदलाव के कारण जारी विज्ञापन अब अमान्य हो गया है, जिसके चलते पूरी भूमि प्रक्रिया को रद्द किया गया है।

नीमा छात्र संघ ने नवीन विज्ञापन पोस्ट में आयुष विभाग को भी समिलित करने की मांग की है। आयोग ने उन अध्यर्थियों को राहत प्रदान की है जिन्होंने इस भर्ती हेतु अनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा किया था, उनके लिए शुल्क

17 साल बाद निकली थी भर्ती

जनकारी के लिए बाद के 17 साल बाद लोक खाद्य स्थाय विकास विभाग की पूछ सेप्टी ऑफिसर (राजपत्रित 3 श्रेणी) की भर्ती निकली थी। जिसे रद्द करके की औपचारिक सुचाना जारी कर दी गई वहीं, विभाग द्वारा बाताया जा रहा है कि जब वहीं नई योग्यतापात्रता कर आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती के लिए नया लोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें करीब दो माह का समय लग सकता है।

वापसी की व्यवस्था की गई है। अध्यर्थी 15 मई 2025 से 30 मई 2025 के बीच आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुल्क वापसी हेतु आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में याचिकाएं लगाकर सभी पक्षों ने खेल अपने लिखित प्रश्न

नए कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की राशि नहीं दे रही सरकार

23 जून को होगी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई

भोपाल, ईमएस।

प्रदेश सरकार द्वारा नए भू-अधिग्रहित जमीन के तहत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देते हुए है। याचिका की सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पक्षों द्वारा विविषित में अपना पक्ष

कानून 2013 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा एक से दो गुना के बीच दिया जाना है। शहरी क्षेत्र से जिन दूरी अधिक होंगी उसी अनुपात से मुआवजा राशि में बढ़ाती होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कीमतें कम होने के कारण यह प्रस्तुत किया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस योगेन्द्र दायर की गई थीं। याचिका की सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पक्षों द्वारा विविषित में अपना पक्ष

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देता है।

प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन की सरकारी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। जिससे ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें बहुत कम मुआवजा गयी याचिका में कहा गया था कि नए भू-अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न